वैकल्पिक प्रोजेक्ट संबंधी बयान
सामाजिक बदलाव के लिए शैक्षिक न्याय: कार्य के लिए एक ढांचा

हम, अधोहस्ताक्षरी लोगों का मानना है कि वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक व्यवस्थाएं शक्ति के उन संबंधों को फिर से उत्पन्न करती हैं जो भीषण असमानताओं को पैदा करती हैं और अंततः धरती पर जीवन के लिए खतरा बन जाएंगी। हम वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र, सुधारात्मक शिक्षा प्रणालियों का समर्थन करते हैं जो एक संपन्न, अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए सामाजिक बदलावों का समर्थन करेंगी।
सह-अस्तित्व और अंतर-संबंधित वैश्विक संकट मानवता और जीवित ग्रह को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक ध्वंस की ओर धकेल रहे हैं। ये संकट - मौजूदा समय में दुनिया भर में कोरोनो वायरस महामारी, संरचनात्मक असमानताओं, पुलिस क्रूरता और नस्लवाद, भीषण पितृसत्ता, जलवायु अराजकता में बढ़ती तेजी और युद्धों के निरंतर बढ़ते खतरे के तौर पर देखे जा रहे हैं- वैश्विक तौर पर पूंजीवाद और सैन्यवाद से संचालित हैं। हमें इस अनोखे ऐतिहासिक मौके का इस्तेमाल सार्वजनिक शिक्षा पर फिर से विचार करके और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन के जरिये गहरे बदलाव के एक ऐसे प्रवेश बिंदु के तौर पर तैयार करना होगा जो मानव एकता और सहयोग का निर्माण करेगा और नस्लवाद, पितृसत्ता और पूंजीवाद को समाप्त करेगा। हम इस धारणा को खारिज करते हैं कि शिक्षा की प्राथमिकता 'मानव पूंजी' का निर्माण करना है; हम इस बात को मजबूती के साथ कहते हैं कि शिक्षा की प्राथमिकताओं में फिर से पैदा होने वाले पारिस्थितिक तंत्र तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए सामाजिक न्याय शामिल होना चाहिए। इसके लिए ऐसी शिक्षा प्रणालियों के निर्माण की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम केवल सभी क्षेत्रों और खासकर अर्थव्यवस्था और राजनीति में सामाजिक परिवर्तन के लिए एक व्यापक संघर्ष के हिस्से के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
नये सामाजिक समझौते बनाने के लिए प्रगतिशील संघर्ष आवश्यक हैं जो कुछ के निहित स्वार्थों के बजाय बहुत सारे लोगों के सामूहिक हितों को साधने का काम करते हैं। मानव इतिहास जटिलता की पूरी एक श्रृंखला और शक्ति संबंधों के जरिये तैयार किए गए अंर्तसंबंधित सामाजिक परिवर्तनों को परिलक्षित करता है: कृषिवाद से लेकर औद्योगीकरण, औपनिवेशिक विजय के रास्ते अधिनायकवादी तानाशाही, पोस्ट उपनिवेशवाद, नव उदारवादी वैश्वीकरण और डिजिटल क्रांतियों और सर्विलांस पूंजीवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति के बीच मिलीभगत जो आज हम लोगों के सामने है।
प्रत्येक नया वर्चस्वशाली वर्ग एक ऐसी विचारधारा को पैदा करता है जो उसके वर्चस्व को बनाए रखने का काम करती है, उन असमानताओं को न्यायोचित ठहराती है जिनका कि यह खुद निर्माण करती है। और इस निराशावाद को बढ़ावा देती है कि परिवर्तन हमेशा संभव है। ये वैचारिक वर्चस्व लगभग हमेशा उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार रहता है और ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करता है जो सुदृढ़, पदानुक्रमित मान्यताओं और कठोर दोहरी अवधारणाओं जैसे मानव/गैर-मानव, पुरुष/महिला, मन/शरीर, धर्मनिरपेक्ष/आध्यात्मिक, श्रेष्ठ/हीन, शहरी/ग्रामीण, हम/वे पर जोर देती है- और मानती है कि उसे जीतने तथा प्राकृतिक दुनिया और सभी जीवित प्राणियों का शोषण करने का अधिकार है। वैश्वीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में उभरते समकालीन अधिनायकवादी, राष्ट्रवादी, पितृसत्तात्मक और बसने वाली औपनिवेशिक आबादी, इन बाइनरी विरोधाभासों को तेज करती है और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सामाजिक असुरक्षा को उकसाने का काम करती है।
आज दुनिया भर की शिक्षा प्रणालियां नवउदार पूंजीवादी और दक्षता के विचारों, लौटने की दर, विकल्प, प्रतियोगिता और आर्थिक प्रगति के नजरिये को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं। यह विचारधारा वैश्विक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों को आकार देने के लिए समृद्ध पराराष्ट्रीय कारपोरेशनों और बेहिसाब शक्तिशाली बिलेनयरों को शामिल करने की क्षमता रखती है जो अंतत: हमेशा निकालने वाला, कार्बन आधारित, आर्थिक गतिविधियां और अबाधित उपभोग और पारिस्थितिक में बेहद पतन के नतीजे के तौर सामने आती है। इस तरह से संगठित हुई शिक्षा प्रणालियां सामाजिक असमानता, बिलगाव और देश के भीतर और राष्ट्रों के पैमाने पर स्तरीकरण को लागू करने के साथ ही उसे वैधता प्रदान करती हैं। फिर भी मौजूदा वर्चस्व को जब तक यह परिलक्षित करती है कि शिक्षा भी मुकाबले का एक बड़ा क्षेत्र है। अधिनायकवादी राज्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए कि शिक्षा बदलाव की एक ताकत हो सकती है धीरे-धीरे इसको नियंत्रण और आज्ञाकारी हथियार के तौर पर उसके निर्माण को सुनिश्चित करते हैं।
नतीजे के तौर पर बहुत सारे बच्चों और युवा लोगों के लिए यह दुनिया बेरंग हो जाती है। उनके द्वारा हासिल की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सामाजिक-आर्थिक स्तरों और उनके परिवारों की भौगोलिक लोकेशन के हिसाब से बंट जाती है। शिक्षा ज्यादातर प्रतियोगात्मक बाजारों में तैयार होती है जो नस्ल, वर्ग और लैंगिक असमानता जहां निजी मालिकान और ठेकेदार

तथा शिक्षक एवं छात्र प्रतियोगिता करते हैं और फिर उनकी लागत क्षमता और मानक टेस्ट के हिसाब से रैंकिंग होती है: एक उपभोक्तावादी शिक्षा मॉडल सीमित सरकारी बजट के मुकाबले मानकों के गठन, मानव पूंजी के निर्माण और लौटने की आर्थिक दर तथा पैसे के मूल्य पर केंद्रित करता है। यह मॉडल मानव अपवादवाद, नस्लीय पूर्वाग्रह और श्वेत प्रभुत्व, मतभेद के नकार, आर्थिक और राजनीतिक असमानता को वैध बनाना, उच्चतम व्यक्तिवाद, अबाधित आर्थिक विकास, बड़े-बड़े दावों का खुला स्वागत और तानाशाही शासन के अनुपालन की व्यवस्था को लागू करता है। इसका एक नतीजा वह विचित्र अंतरविरोध है कि मानव इतिहास में सबसे ज्यादा शिक्षित आबादी सामूहिक रूप से जीवित ग्रहों की प्रणालियों की पारिस्थितिकी के ध्वंस का कारण बन रही है जो सामूहिक आत्महत्या और पारिस्थितिकी के खात्मे का रास्ता है।
पिछले तीस सालों के दौरान सिविल सोसाइटी और शैक्षिक यूनियनें सभी के लिए शिक्षा की आकांक्षा की लगातार एडवोकेसी करती रही हैं: अनिवार्य शिक्षा का अभूतपूर्व पैमाने के स्तर पर विस्तार हो गया है- जिसमें तकरीबन रोजाना 200 करोड़ बच्चे शामिल होते हैं। ज्यादातर परिवार अब ऐसा मानते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए 8-12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरा करना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर सरकारें मानती हैं कि बच्चों और युवाओं को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना एक अच्छी सरकारी नीति है। लेकिन हम लोग इसको हासिल करने के मामले में इसके आस-पास भी नहीं हैं। कुछ हिस्से में, पिछले चार दशकों के बाजार के कट्टरतावाद के चलते बड़े पैमाने पर सामने आए संरचनात्मक अन्याय ने सामाजिक क्षेत्रों में लगातार खर्चे को कम किया है और सभी तरह के सरकारी गतिविधियों को अप्रभावी और नाजायज के तौर पर पेश कर अपमानित किया है। नतीजे के तौर पर शिक्षा के ऊपर खर्चा बेहद अपर्याप्त हो गया है और ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। राष्ट्रीय सरकारों और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए यह संभव भी है।
ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है; सरकारों के पास हमेशा सेना, पुलिस, सुरक्षा और खुफियागिरी और कारपोरेट कल्याण पर खर्च करन के लिए पैसा होता है। इस विचार से लड़ने की दिशा में हमें नवउदारवादी निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कमी को एक मिथक के तौर पर और आत्मसंयम को एक सोचे-समझे गए नीतिगत विकल्प के रूप में पेश किए जाने का पर्दाफाश करना होगा। हालांकि शिक्षा पर खर्चे के लक्ष्य को पूरा करने के मामले में एक वैश्विक सहमति है। यहां तक कि ज्यादातर सरकारें अपने बजट का 20 फीसदी और जीडीपी के 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च के अपने लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पातीं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने दशकों से अपनी जीडीपी का 0.7 फीसदी सरकारी विकास सहायता पर खर्च करने का वादा किया था लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा ही उसके लिए आवंटित कर पाता है। और ये सभी लक्ष्य जरूरत को बहुत कम करके आंकते हैं।
हमें इन तर्कों को सार्वजनिक तौर पर भी स्थापित करना होगा। समस्या फंडिंग के पार है। आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नव उपनिवेशवादी संस्थाएं हैं जो पूरे विश्व में नव उदार, तथाकथित वाशिंगटन आम सहमति की नीतियों को बढ़ावा दे रही हैं। शिक्षा विभाग की नीतियों (और दूसरी सामाजिक) को प्रभावित करने में आईएमएफ और विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा में सहयोग देने के बजाय आईएमएफ वास्तव में देशों को शिक्षकों और दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के वर्करों को हायर करने पर रोक लगा रहा है। विश्व बैंक वस्तुपरक सलाह के लिए एक रिसर्च आधारित संस्था होने का बहाना बनाता है लेकिन उसकी पिछले चार दशकों की संस्तुतियां नव उदार विचारधारा पर आधारित हैं। आईएमएफ और विश्व बैंक में ओवरहालिंग के लिए एक नयी ब्रेटन वुड कांफ्रेंस बुलाने का यह सबसे बेहतरीन समय है।
हम क्रांतिकारी बदलाव का आह्वान करते हैं। सभी सरकारों को शुरुआती बच्चों से लेकर उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए जो एक महत्वपूर्ण, सहभागी, हम कैसे सोचते हैं उसका लोकतांत्रिक पुनर्मूल्यांकन करने और दुनिया में एकजुट होकर काम करने के योग्य बनाएगा। शिक्षा को एक मानव अधिकार के तौर पर मुहैया कराने के लिए एक पूरी तरह से पब्लिक फंडेड सिस्टम होना चाहिए जो राष्ट्रीय और वैश्विक प्रगतिशील, पुनर्वितरणकारी कर प्रणालियों के जरिये टिकाऊ आधार पर वित्त पोषित हो। और यह सब कुछ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की शर्तहीन सहायता के साथ हो। लेकिन पाठ्यक्रम को पूरी ताकत से उपभोक्ता जटिलता को विनम्रता पूर्वक खारिज कर देना चाहिए जो ग्लोबल वार्मिंग और तबाही को बढ़ावा देने का काम करते हैं। समुदाय में बिल्कुल धंसी हुई शिक्षा को सांस्कृतिक तौर पर प्रासंगिक और नस्लवाद विरोधी, लैंगिक असमानता विरोधी, सहयोगी, सामाजिक एकजुटता, प्रेम, कल्पना, सृजनात्मकता, निजी संतुष्टि, शांति, पर्यावरणपक्षी मानसिकता और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। अध्यापकों को पेशागत स्वायत्तता, गुणवत्तापरक कार्यस्थितियां और यूनियन तथा दूसरे संगठनों के जरिये नीति निर्माण में मुख्य आवाज के तौर पर शामिल किए जाने की जरूरत है। उसी तरह से छात्रों और उनके प्रतिनिधि संगठनों को राजनीतिक और शिक्षा शास्त्र संबंधी फैसले में भी आवाज होनी चाहिए इसके अलावा उनकी अपनी भागीदारी के अधिकार का उनको ज्ञान होना चाहिए।

दुनिया को शिक्षा के क्रांतिकारी पुनर्दृष्टि की जरूरत है जो पुनर्उत्पादक समाजों को बनाने और उनको बदलने में बेहद सहायक साबित होगी। इसके लिए एक नये सामाजिक समझौते की जरूरत होगी जो सैन्य और सुरक्षा संबंधी खर्चों के मुकाबले सामाजिक खर्चों को तरजीह देता है और व्यवसायिक क्षेत्र के तंग हितों के पार जाता है। जिसमें इडटेक फर्म्स, निजी स्कूलों की श्रृंखलाएं और दूसरे शिक्षा से जुड़े व्यवसायिक खिलाड़ी शामिल हैं। हम शिक्षा के निजीकरण और दूसरी सामाजिक सेवाओं की दिशा को बिल्कुल उलट देने क आह्वान कर रहे हैं। जिसमें शिक्षा और नीतिगत निर्माण में व्यवसाय के तर्क को बिल्कुल बाहर रखा जाना है। इसके बजाय हम संगठित छात्रों और अध्यापकों, पूरे ट्रेड यूनियन आंदोलन, लोकतांत्रिक समुदाय आधारित आंदोलनों- जिसमें अल्पसंख्यकों के संगठन, प्रवासी और शरणार्थी शामिल हैं- और स्वतंत्र मीडिया, संगठनों और प्रोफेशनल जो गलत चीजों में हमारे न्याय बढ़ाने के संकल्पों को साझा करते हैं, वास्तविक समाज जिसमें हम रहते हैं, के संघर्षों पर जोर देते हैं और उनसे सबक सीखते हैं। ये समूह पहले ही शैक्षिक न्याय के लिए विकल्प विकसित कर चुके हैं जिसमें स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा प्रोग्राम शामिल हैं जो 21 वीं सदी के समाजवादी, स्थानीय और ब्लैक संप्रभुता, ब्लैक लाइव्स मैटर, दास-प्रथा विरोधी और महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र को समर्थन करता है।

शिक्षा में न्याय चार क्षेत्रों में जस्टिस से संबंधित न्याय को आगे बढ़ाने पर निर्भर करता है:

सामाजिक न्याय- शिक्षा का निर्माण समानता, बदलाव और पुनर्उत्पादक जीवन के लिए

शिक्षा प्रणालियों को उस नई दिशा में ले जाने की जरूरत है जो अपने समाजों की असमानताओं और अन्यायों, नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा, लैंगिक और विकलांगता न्याय को हल करे और ऐसे मॉडल को शामिल करने की जरूरत है जो इस बात की शिक्षा देता है कि कैसे सामुदायिक रूप से काम करते हुए शिक्षा और समाज को बदलाव की तरफ ले जाना है।

जलवायु न्याय- इस बात को सीखना कि धरती पर कैसे हम पुनर्उत्पादक जीवन गुजार सकते हैं

हमें वैश्विक स्तर पर एक नई ग्रीन डील और सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों की जरूरत है जो मानव पारिस्थितिकी और गुणों के पक्षपोषण की शिक्षा देती है जो आज के और भविष्य दोनों में बदलावों के लिए सुविधा प्रदान करेगी।

आर्थिक न्याय- बदली हुई अर्थव्यवस्था में शिक्षा और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं का वित्तपोषण

आर्थिक प्रणाली को लाभ के बजाय समानता और अवसर पर केंद्रित करते हुए सभी लोगों की असली जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इस महामारी को पूंजीवाद से बिल्कुल दूर एक बुनियादी बदलाव और कार्यस्थलीय लोकतंत्र तथा रेडिकल रूप से एक पुनर्वितरित अर्थव्यवस्था वाले दौर के तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी की सेवा के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रोग्रेसिव खर्चे को प्राथमिकता देता हो।

राजनीतिक न्याय- सभी स्तरों पर राजनीतिक रिश्तों का पुनर्गठन

हमें सर्वसत्तावादी और उन्मादी राष्ट्रवाद से दूर जाने की जरूरत है। हमें वैश्विक एकजुटता को ऊर्जावान बनाने, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर अलग-अलग हिस्सों में चलने वाले ग्रासरूट आंदोलनों को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। हमें स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर और ज्यादा समावेशी और भागीदारी लोकतंत्र को विकसित करने की जरूरत है।

ये शुरुआती विचार कोई दूरस्थ, काल्पनिक मृगतृष्णा नहीं हैं; इसकी बजाय ये दुनिया के बहुत सारे प्रगतिशील समूहों और संगठनों के विचारों और कार्यवाहियों के आधार पर निर्मित किए गए हैं। हम अधोहस्ताक्षरी इन विचारों को धरती के सामने आए गहरे संकट का मुकाबला करने के लिए शिक्षा और समाज के आमूलचूल पुनर्दृष्टि को एक जरूरी दिशा के तौर पर देखते हैं-